असर न्यूज़

Email: asarnewsinfo@gmail.com
RNI. NO. DELHIN/68203/98

Web: www.asarnews.com

दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष: 29 अंक: 27 सोमवार, 06 जुलाई से 12 जुलाई 2026 मूल्य: 2 रू. पृष्ठ:04

भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी के नए युग की शुरूआत : पीएम मोदी

भारत-जापान साझेदारी को नई दिशा, ऊर्जा से रक्षा तक बढ़ेगा सहयोग

नई दिल्ली। तीन दिवसीय भारत दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को 'छोटी बहन' बताते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें दूरदर्शी व लोकप्रिय नेता बताया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच आपसी विश्वास दोनों देशों की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी है और यही साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

भारत-जापान की साझेदारी में विश्वास सबसे बड़ी ताकत : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आप जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एक दूरदर्शी तथा लोकप्रिय नेता भी हैं। आप जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत-जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।' उन्होंने जी7 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा, 'कुछ ही दिन पहले जी7 शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था कि मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल के दौर में आपसी विश्वास हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी है। मुझे गर्व है कि भारत-जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान भारत की विकास यात्रा का अहम भागीदार रहा है। प्रधानमंत्री ताकाइची की यात्रा से हमारी स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरूआत हो रही है।'

इंडो-पैसिफिक में शांति और समृद्धि पर जोर

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं तथा स्वतंत्र, समृद्ध और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दोनों देश मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान की टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भविष्य में सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। उन्होंने बताया कि एआई के क्षेत्र में दोनों देशों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है और भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों ने अपने जापानी साझेदारों के साथ समझौते किए हैं। उन्होंने कहा, 'जापान की प्रीसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।'

रक्षा सहयोग में नया अध्याय

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत और जापान के पहले को-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है। उन्होंने बताया कि नेवल रेडियो एंटीना परियोजना दोनों देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी में नया अध्याय खोलेगी। साथ ही भविष्य में दोनों देश क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने वाली रक्षा तकनीकों का संयुक्त विकास करेंगे।

स्वास्थ्य और निवेश सहयोग को भी मिलेगी मजबूती

पीएम मोदी ने कहा कि फार्मा, मेडिकल उपकरण और बायोटेक क्षेत्र में हुए समझौते वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की उत्पादन क्षमता और जापान की गुणवत्ता को जोड़कर दुनिया को किफायती, विश्वसनीय और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में 100 से अधिक नए कारोबारी समझौते हुए हैं, जिनसे भारत में 10 बिलियन डॉलर से अधिक का जापानी निवेश आएगा। साथ ही वित्तीय सेवा एजेंसियों के बीच हुए समझौते से पूंजी निवेश को और गति मिलेगी।

10 ट्रिलियन येन निवेश का रखा लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश और भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में लगातार हो रहे सुधारों से कारोबार करना आसान हुआ है और जापानी कंपनियां इसका लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक सुरक्षा के संयुक्त रोडमैप के तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैटेरियल्स और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा।

ऊर्जा और हरित विकास में बढ़ेगा सहयोग

पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इंडिया-जापान बायोगैस इनिशिएटिव के तहत भारत में 1,000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे गोवर्धन पहल को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे।

विकसित भारत-जी राम जी के लिए राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रविवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा राज्यों को योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ की पहली किस्त (मदर सैंक्शन) जारी की।इस दौरान, चौहान ने कहा कि सरकार का संकल्प था कि 1 जुलाई, 2026 से विकसित भारत-जी राम जी पूरे देश में बिना किसी व्यवधान के लागू हो। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि योजना पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है तथा मनरेगा से विकसित भारत-जी राम जी में ट्रांजीशन पूरी तरह सहज और सुचारु रहा है। अब तक किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा संचालन संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर भाई-बहनों की सेवा ही भगवान की सेवा है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, समय पर मजदूरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण

सुनिश्चित करना है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब देश के किसी भी राज्य में मजदूरी 300 प्रतिदिन से कम नहीं होगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण श्रमिकों की आय और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। चौहान ने आगे कहा कि आज जारी की गई 25,863 करोड़ की पहली किस्त का उद्देश्य राज्यों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे भी अपनी हिस्सेदारी की राशि समय पर जारी करें, जिससे मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकसित भारत-जी राम जी के प्रभावी क्रियान्वयन में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पहली किस्त राज्यों की मांग के आधार पर जारी की गई है और भविष्य में भी आवश्यकता के अनुसार धन उपलब्ध कराया जाएगा। चौहान ने कहा कि ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों का चयन करें ताकि गांवों का समग्र और सहभागी विकास सुनिश्चित हो सके।

आंध्र प्रदेश से विकसित भारत-जी राम जी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव से 'विकसित भारत-जी राम जी योजना' का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान सहित सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार, ग्राम विकास और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नई योजना की शुरूआत की गई।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन की शुरूआत 'नमः वेंकटेश्वराय' और 'गोविंदा-गोविंदा' के जयकारों के साथ की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना गरीबों और मजदूरों के लिए भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी मिले तथा देश का कोई भी गरीब मजदूर बिना रोजगार के न रहे।शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जबकि विकसित भारत-जी राम जी योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि गरीबों के प्रति सरकार की सोच में बदलाव का प्रतीक है।

संपादकीय

रक्षा से परमाणु ऊर्जा तक बढ़ा सहयोग

वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अलग-अलग देशों में आपसी सहयोग के लिए जिस स्तर पर नए समीकरण बन रहे हैं, उससे साफ है कि अब पुराने ध्रुवों के विकल्प तैयार हो रहे हैं और विकसित तथा सक्षम देशों को भी अपने बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में देखें, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को जिस स्तर पर सहयोग और साझेदारी की घोषणा हुई, वह मौजूदा दौर की जरूरतों के मद्देनजर एक महत्त्वपूर्ण पहल है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय के दौरान मुक्त व्यापार के क्षेत्र में भारत ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं, जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए नई संभावनाएं तैयार करने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने जैसे कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। साथ ही परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढ़ाने का खाका भी पेश किया गया। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने तथा अन्य मोर्चों पर जारी तनावों के हल के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयास जारी रखने पर भी सहमति बनी। जाहिर है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी के सफर के विस्तार की जो पहल हुई है, उसका आधार अगले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर बदलते ध्रुव और उसी मुताबिक तैयार होते समीकरण हैं, जिनमें सहयोग के नए आयाम तैयार हो रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का पहले से ही साझेदारी का लंबा सफर रहा है, लेकिन ताजा समझौतों में परमाणु ऊर्जा और दुर्लभ खनिजों के मामले में सहयोग के जिस मोर्चे पर ठोस समझदारी बनी है, वह आने वाले वक्त में बेहद अहम साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया भर के यूरेनियम संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा है, मगर कुछ कानूनी और तकनीकी अड़चनों की वजह से भारत को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका। अब ताजा समझौते के बाद भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन का एक अहम स्रोत मिल सकेगा। हालांकि मौजूदा दौर में विश्व जिस स्तर के तनावों से गुजर रहा है, उसमें यूरेनियम के उपयोग को लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं। मगर इस मसले पर दोनों देशों ने यह साफ किया है कि सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात की अनुमति होगी और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तय सुरक्षा प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही दोनों देश खनिज गलियारे को विकसित करने के क्षेत्र में भी साझेदारी करेंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी। समुद्री सुरक्षा सहयोग के मसले पर हुए समझौते के बाद यह भी उम्मीद की जा रही है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए साझा प्रयासों को नई रफ्तार मिलेगी और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बरक्स संतुलन का एक मोर्चा खड़ा किया जा सकेगा। जाहिर है, दोनों देशों के बीच संबंधों में विविधता लाने पर जोर देने के प्रयासों के तहत सहमति बनी है। मगर यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि इसका मूल आधार एक-दूसरे की जरूरतों के लिए समानता पर आधारित आर्थिक सहयोग हो और यह भारतीय हितों को सुनिश्चित करने वाला हो।

दिल्ली: वायु प्रदूषण के साथ ओजोन प्रदूषण की चुनौती

ललित गर्ग

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंटू वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यतः पीएम 2.5, पीएम 10, पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही, लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है-भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे-धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को। जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उपभोग की वर्तमान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा। दिल्ली आज केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बन चुकी है। गर्मियों में बढ़ते तापमान, तेज धूप और वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से भूतलीय ओजोन बनती है। यह वही ओजोन नहीं है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। धरातल पर बनने वाली ओजोन एक विषैली गैस है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता कम करती है, दमा के रोगियों की स्थिति बिगाड़ती है, आँखों में जलन पैदा करती है तथा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाती है। आज दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल वाहन नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है। वास्तविक संकट अनियोजित शहरीकरण का है। पिछले दो दशकों में दिल्ली और उससे लगे क्षेत्रों में जिस तेजी से खेत, तालाब और हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदले हैं, उसने प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुँचाया है। जहाँ कभी वर्षा का पानी धरती में समा जाता था, वहाँ अब सीमेंट और डामर की सतह है। पारंपरिक जलस्रोत मिट गए, पेड़ों की संख्या घटी और गर्मी बढ़ती गई। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक रहने लगा है। यही अतिरिक्त गर्मी ओजोन बनने की प्रक्रिया को और तेज करती है। आज महानगरों का विस्तार विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, उद्योग चाहिए। इन सबके लिए खेत समाप्त हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जलस्रोत नष्ट हो रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल, मिट्टी और जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है।

विकास की यह दिशा अंततः मानव जीवन के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्ता अभी भी इतनी प्रभावी नहीं हो सकी कि लोग निजी वाहनों का त्याग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्वागतयोग्य है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजली यदि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आएगी तो प्रदूषण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित परिवहन को समानांतर गति से बढ़ाना आवश्यक है। ओजोन प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु अब समय आ गया है कि इसकी रणनीति का विस्तार किया जाए। केवल पार्टिकुलेट मैटर पर ध्यान देने के बजाय ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषकों की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण पर भी समान बल देना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अधिक व्यापक, आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा। समस्या के समाधान में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, खुले में ईंधन जलाना, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का अनुचित निस्तारण जैसी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइकिल और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, हरित पट्टियों का विकास और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन भी प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट भी है। बढ़ती बीमारियाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ डालती हैं, कार्यक्षमता घटाती हैं और करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदूषण बच्चों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका कहीं अधिक गंभीर मूल्य चुकाना पड़ेगा। भौतिकशास्त्र दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम स्वागतयोग्य हैं और उनसे सकारात्मक परिणामों की आशा की जा सकती है, किंतु यह तभी संभव होगा जब केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज मिलकर समन्वित प्रयास करें। प्रदूषण किसी एक सरकार, एक मौसम या एक कारण की समस्या नहीं है।

सूरज नांबियार से सेपरेशन के बाद बोलीं मौनी राय

मैं आसानी से माफ कर देती हूं

अपने पति सूरज नांबियार से अलग होने की घोषणा के कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस मौनी रॉय ने माफी, भावनात्मक घावों और मुश्किल अनुभवों से उबरने में आध्यात्मिकता की भूमिका के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि समय के साथ माफी को लेकर उनकी समझ कैसे बदली है। इस बीच वो एक्टिंग में भी लगातार सक्रिय हैं।

बातचीत में मौनी रॉय ने कहा कि कम उम्र में भी लोगों को माफ करना कभी मुश्किल काम नहीं था। असली चुनौती तो उसके बाद भी रह जाने वाले दर्द को भूलना थी। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं बहुत आसानी से माफ कर देती थी और आज भी करती हूं, लेकिन मैं भूल नहीं पाती थी। अब अपनी पर्सनल और आध्यात्मिक यात्रा के साथ मुझे लगता है कि बस माफ कर देना चाहिए। भगवान ही आपको भुलाने में मदद करते हैं।

ज्यादा तकलीफ उसे होती है, जो छोड़ नहीं पाता

मौनी ने माफी को एक ऐसी प्रक्रिया बताया जो तब आसान हो जाती है, जब आप दुख को हमेशा ढोते रहने वाली चीज मानना छोड़ देते हैं। उनके अनुसार, नाराजगी को मन में बनाए रखने से अक्सर उसी व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ होती है जो उसे छोड़ नहीं पाता। अगर आप इसे जाने नहीं देंगे, तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही होगी। उन्होंने उस असंतुलन के बारे में भी बात की जो अक्सर किसी के दुख पहुंचाने के बाद पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जिसे दुख पहुंचा है, वह उस अनुभव को लंबे समय तक बार-बार याद करता रह सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उससे आगे बढ़ चुका होता है। कभी-कभी जिस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया होता है, वह इसके बारे में सोच भी नहीं रहा होता, चाहे उन्होंने आपको कितना भी गहरा दुख क्यों न दिया हो।

मेडिटेशन ने बदला नजरिया

एक्ट्रेस ने हाल के साल में ज्यादा शांति और स्पष्टता पाने का श्रेय मेडिटेशन, मंत्र-जाप और आध्यात्मिकता जैसी चीजों को दिया। उन्होंने बताया कि इन अनुभवों ने रिश्तों, निराशा और इमोशनल रिकवरी के प्रति उनके नजरिए को बदल दिया है।

साथ ही मौनी ने यह भी साफ किया कि माफ करने का मतलब नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को नजरअंदाज करना या उसके अस्तित्व को नकारना नहीं है। उन्होंने किसी व्यक्ति को जज करने और नुकसानदेह कामों या आदतों को पहचानने के बीच फर्क बताया। उन्होंने समझाया कि कुछ बुरे लोग होते हैं जो आपको दुख पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं उस व्यक्ति को बुरा नहीं कह रही हूं, बल्कि उनकी आदतों को बुरा कह रही हूं।

'अब होगा हिसाब' में नजर आई मौनी

वर्कफ्रंट की बात करें तो मौनी रॉय आखिरी बार 'अब होगा हिसाब' में नजर आई हैं। इसमें उनके साथ शाहिर शेख, संजय कपूर और अविनाश मिश्रा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। इससे पहले मौनी वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में भी नजर आई थीं।

अब कॉमेडी करना मुश्किल हो गया है

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज की तैयारी में लगे हैं। फिल्म का प्रमोशन जोरों पर चल रहा है। इस कॉमेडी फिल्म में बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी। अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अक्षय कुमार का मानना है कि डिजिटल दौर में कॉमेडी करना ज्यादा मुश्किल हो गया है। जहां मीम्स और इंस्टाग्राम रील्स रोजाना लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। एक्टर ने स्टैंड-अप कॉमेडियंस की भी तारीफ की कि वे किस तरह लोगों को हंसाते हैं।

आज हर जगह रील्स और मीम्स के जरिए कॉमेडी कंटेंट मौजूद है बातचीत में अक्षय ने माना कि मौजूदा वक्त में कॉमेडी करना काफी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह अब और भी मुश्किल हो गया है। आज हर जगह रील्स, मीम्स और कॉमेडी कंटेंट मौजूद हैं। लेकिन कॉमेडी एक बड़ी नदी की तरह है; यह कभी सूखती नहीं है। कॉमेडी के कई रूप हैं, जैसे फिजिकल कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, स्लॅपस्टिक कॉमेडी और डार्क ह्यूमर। एक्टर ने भारत में पिछले कुछ साल में कॉमेडी के नए तरीकों जैसे स्टैंड-अप के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को हंसाने के अनगिनत तरीके हैं।

अगर आप इंस्टाग्राम खोलें, तो आपको ढेर सारे मीम्स और मजेदार वीडियो मिल जाएंगे। लोग रोजाना कॉमेडी देखते-सुनते हैं। बहुत सारे कॉमेडी शो और टैलेंटेड स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं जो नया कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन लोगों को हंसाना आज भी सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लोग अक्सर कॉमेडी को कमतर आंकते हैं। मैं स्टैंड-अप कॉमेडियन का बहुत सम्मान करता हूं। दर्शकों के सामने अकेले खड़े होकर लोगों को हंसाना वाकई बहुत मुश्किल काम है।

इमरान हाशमी की फिल्म 'रूह' की हुई घोषणा

हॉरर फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी करने वाले अभिनेता इमरान हाशमी पांच वर्षों के बाद एक बार फिर हॉरर जॉनर फिल्म में नजर आने वाले हैं। उनकी नई फिल्म 'रूह' की घोषणा हो चुकी है। मेकर्स ने इसका पहला लुक भी जारी किया है। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि यह कब रिलीज होगी।

फिल्म के मेकर्स ने एक वीडियो के जरिए फिल्म 'रूह' की घोषणा की है। 52 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जंगल में एक रहस्यमयी लड़की है। इसके बाद एक धुंधला सा शीशा नजर आता है। इस शीशे को एक रहस्यमयी हाथ साफ करता है। शीशे में इमरान हाशमी का चेहरा नजर आता है। देखते-देखते इमरान हाशमी की आंखें काली हो जाती हैं। इसके बाद फिल्म का टाइटल 'रूह' लिखा नजर आता है।

कब रिलीज होगी फिल्म?

मेकर्स ने वीडियो में ही बताया है कि यह फिल्म 2027 में रिलीज होगी। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक मयंक शर्मा होंगे। इसके लेखक मयंक शर्मा और विशाल कपूर हैं। फिल्म के निर्माता विक्रम खंखर और सनी खन्ना होंगे।

र सुब्बू का हिस्सा ना मेरे लिए बेहद ांचक अनुभव रहा

थिला पालकर अपनी आगामी स्ट्रीमिंग सीरीज की रिलीज की तैयारी में हैं। अभिनेत्री का कहना ीरीज में उनका किरदार हास्य और वास्तविक वनाओं के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित करता ंदीप किशन और मुरली शर्मा भी अहम भूमिकाओं ंगे। कहानी सुब्रमण्यम 'सुब्बू' चिल्लुकुरी राव के इर्द-, जिसकी पोस्टिंग काल्पनिक गांव माकीपुर में होती है, शिक्षक जाना नहीं चाहता। सुब्बू अपने परिवार के न बनाए रखने के इरादे से गांव पहुंचता है और पढ़ाने के हता है, लेकिन उसे गांव में सबसे असहज जिम्मेदारी एजुकेशन पढ़ाने का काम सौंप दिया जाता है।

पने किरदार को लेकर मिथिला पालकर ने कहा, सुब्बू' की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली कि यह हास्य के साथ-साथ वास्तविक मानवीय भी खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। इस यात्रा में हर यादगार लेकर आता है।' उन्होंने आगे कहा, 'ऐसी हिस्सा बनना जो मनोरंजक होने के साथ-साथ सार्थक लिए बेहद रोमांचक अनुभव रहा। नेटफ्लिक्स के साथ हमेशा घर वापसी जैसा महसूस होता है। मैं उनके रिजिनल शो लिटल थिंग्स का हिस्सा रही हूं और अब तेलुगु ओरिजिनल सीरीज 'सुपर सुब्बू' से जुड़ना है जैसे यह सफर पूरा चक्र पूरा कर चुका हो।

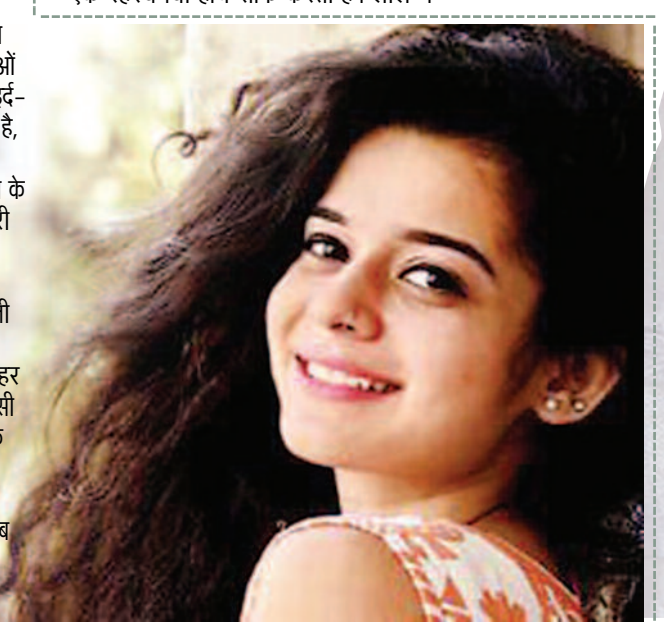

घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की रणनीति को अमित शाह की मंजूरी

अवैध नागरिकता और फर्जी पहचान पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू

नई दिल्ली। घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। देश में अवैध घुसपैठ और बदलती जनसंख्या संरचना पर केंद्र सरकार पूरी तरह आक्रामक मोड़ में आ चुकी है। जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को अपनी पूरी रणनीति बता दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने घुसपैठियों का दाना पानी बंद करने की दिशा में सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। लाखों संदिग्ध लाभार्थियों के नाम सरकारी योजनाओं से हटाए जा चुके हैं और नागरिकता की कड़ी जांच शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार अब साफ संकेत दे चुकी है कि अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की हर कोशिश पर निर्णायक प्रहार होगा।

हम आपको बता दें कि जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की। समिति ने साफ कर दिया है कि वह देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर जमीनी सच्चाई का प्रत्यक्ष अध्ययन करेगी, ताकि अवैध घुसपैठ, संदिग्ध नागरिकता और जनसंख्या असंतुलन जैसे गंभीर मुद्दों पर ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकें। समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले ही विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए प्रश्नावली तैयार कर ली गई है। इसके जरिये स्थानीय प्रशासन, सरकारी विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों से विस्तृत तथ्य जुटाए जाएंगे। गृहमंत्री ने समिति की रणनीति की सराहना करते हुए गृह सचिव को निर्देश दिया है कि समिति को हर स्तर पर पूरा सहयोग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने समिति से जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने को कहा है। यह पूरा अभियान उस 'हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन' का हिस्सा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को की थी। मोदी सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है।

इसी दिशा में पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ते हुए लाखों संदिग्ध लाभार्थियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया है कि अन्नपूर्णा योजना के लिए आए लगभग एक करोड़ साठ लाख आवेदनों में से करीब छब्बीस लाख आवेदन नागरिकता संबंधी जांच में खारिज कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन लोगों ने तय मानकों को पूरा नहीं किया।शुभेन्दु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि पूर्ववर्ती लक्ष्मीर भंडार योजना में भारी स्तर पर फर्जी लाभार्थी शामिल थे। जांच में ऐसे लाखों नाम सामने आए जो या तो मतदाता सूची से हटाए जा चुके थे, या दूसरे स्थानों पर जा चुके थे, या फिर एक से अधिक खातों में सरकारी सहायता ले रहे थे। कई मामलों में मृत लोगों के नाम पर भी सहायता जारी थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले- संकट में भी जनता पर नहीं पड़ने दिया बोझ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुए 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का भारत ने इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नीतियों और प्रभावी कूटनीति के दम पर सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं करती, बल्कि उन्हें समय पर पूरा भी करती है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान रिफाइनरी, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल, उड़ान योजना, जयपुर मेट्रो विस्तार और

शेखावटी जल परियोजना समेत कई विकास कार्यों का उल्लेख किया।प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की धरती ने हमेशा स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल, उड़ान योजना के नए चरण, जयपुर मेट्रो विस्तार और शेखावटी क्षेत्र की जल परियोजना जैसे कार्य राजस्थान के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने 54 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र मिलने पर भी बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत ने समय रहते सही निर्णय लेकर इस संकट का प्रभाव कम किया।

पहले खत्म करो आतंकवाद, फिर होगी सिंधु जल समझौते पर बात, भारत की पाकिस्तान को दो टूक

नई दिल्ली। भारत ने आज शुक्रवार 3 जुलाई को सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देने की वजह से सिंधु जल संधि (IWT) पर भारत का रुख फिलहाल रुका हुआ है। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'सिंधु जल संधि पर भारत का रुख एक जैसा है। पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने के जवाब में Indus Waters Treaty फिलहाल रुकी हुई है।' विदेश

मंत्रालय की तरफ से तीस्ता नदी परियोजना पर भी जवाब दिया गया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने प्रस्तावित तीस्ता नदी परियोजना पर बांग्लादेश को अपना पक्ष पहले ही बता दिया है।

देश की सुरक्षा होगी और मजबूत, 52,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली। देश के सशस्त्र सैन्य बलों को और अधिक आधुनिक व शक्तिशाली बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लगभग 52,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत रक्षा खरीद परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी (एओएन) प्रदान की गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में स्वीकृत इन प्रस्तावों का उद्देश्य तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता, निगरानी व्यवस्था, वायु रक्षा और भविष्य के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है। डीएसी ने भारतीय सेना के लिए कई महत्वपूर्ण प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें एंटी-ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 'आकाश तरंग', मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से

हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली शामिल हैं। 'आकाश तरंग' प्रणाली सेना की अग्रिम तैनातियों और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को दुश्मन के ड्रोन हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगी। यह प्रणाली ड्रोन का पता लगाने, उन्हें बाधित करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। वहीं, एंटी-टैंक मिसाइल से इन्फेंट्री की ताकत बढ़ेगी। मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली सेना की इन्फेंट्री टुकड़ियों को दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अधिक प्रभावी बनाएगी। इससे अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन तथा अन्य हवाई खतरों को रोकने में अहम भूमिका निभाएंगी। बहु-स्पेक्ट्रल सेंसर से लैस नई प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक बाधाओं के बावजूद प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी। सक्रिय सुरक्षा प्रणाली टैंकों की ओर आने वाली मिसाइलों और रॉकेटों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर सकेगी। इससे युद्धक्षेत्र में टैंकों के सुरक्षित बने रहने की क्षमता बढ़ेगी। वहीं, नई पीढ़ी के जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम होंगे। ये अधिक गति, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता, अधिक मारक शक्ति और कम लागत के कारण भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय नौसेना के लिए बहु-प्रभावी समुद्री माइन, नौसैनिक जहाजों से संचालित मानवरहित हवाई प्रणाली तथा विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए भूमि आधारित परीक्षण सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। बहु-प्रभावी समुद्री माइन दुश्मन के युद्धपोतों और नौसैनिक अभियानों की स्वतंत्र आवाजाही को सीमित करने में मदद करेगी।इससे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा और मजबूत होगी। उन्नत सेंसरों से लैस नई मानवरहित हवाई प्रणाली नौसेना को समुद्र में दूर तक निगरानी रखने, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और वास्तविक समय में जानकारी जुटाने में सहायता देगी। नई प्रणोदन प्रणाली के लिए स्थापित की जाने वाली परीक्षण सुविधा, नौसेना के भविष्य के जहाजों और प्रणालियों के परीक्षण तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक रजनीकान्त तिवारी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स ए-9 सराय पीपल थला एक्सटेंशन दिल्ली-110033 से छपवाकर कार्यालय असर न्यूज सी-21, नेताजी रोड, आदर्श नगर दिल्ली-110033 से प्रकाशित किया। किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा दिल्ली की अदालत में होगा तथा किसी भी प्रकाशित लेखन सामग्री से प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। R.N.I. No. DELHIN/68203/98